टोंकिन संकट के प्रसंग में

शिवदास घोष

टोंकिन संकट के प्रसंग में

1964 के टोंकिन संकट की पृष्ठभूमि में लिखे गये इस लेख में ख्रुश्चेव के नेतृत्व वाले सोवियत नेतृत्व की आत्म-समर्पणकारी नीति और साथ ही ताप-नाभिकीय युद्ध के संशोधनवादियों के डर का भरपूर फायदा उठाने वाली अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा चलाई गयी डाकेजनी की नीति का पर्दाफाश किया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन्सन के आदेश पर, पिछले 4 अगस्त को अमेरिकी नौसेना ने वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की दो टॉरपीडो नौकाओं को डुबो दिया। उसके अगले दिन कई जेट हवाई जहाज अमेरिकी सातवें जहाजी बेड़े से उड़े, वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, गियान्ह नदी के मुहाने और होंग-गाइ शहर के करीब विन्ह-बेन-थूय इलाके पर गोलीबारी और बमबारी की, जिससे उसके तटीय ठिकानों उपकरण-स्थापनाओं (इन्सटालेशनों) की भारी तबाही हुई और कई जानें गयीं। यह बात सही है कि अमेरिका द्वारा वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की हवाई सीमा का उल्लंघन और उसके इलाकों पर बमबारी कोई नयी बात नहीं है। अमेरिकी आक्रमणकारियों ने अतीत में भी ऐसा किया है। 4 अगस्त के आक्रमण से चंद दिन पहले, अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने लाओस की सीमा पर स्थित वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के दो इलाकों—नाम-कन और नूंग-दे पर गोलीबारी और बमबारी की थी। इसके अलावा अमेरिका ने युद्धपोत भी रवाना कर दिये थे, जिन्होंने गैर-कानूनी तरीके से उत्तरी वियतनाम की समुद्री सीमा में प्रवेश करके होन-नू और होन-मे द्वीपों तथा अन्य तटवर्ती इलाकों पर गोलाबारी की थी। लेकिन अमेरिका द्वारा हाल ही में पिछले अगस्त में किये गये आक्रमणों का कोई जोड़ नहीं है। अपनी इन करतूतों से अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सभ्यता के सभी नियम-कायदों का उल्लंघन किया है और कमजोर देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को, विशेष रूप से एशिया की शांति और सामान्य रूप से विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। यही कारण है कि दुनिया भर की साम्राज्यवाद-विरोधी और शांति चाहने वाले ताकतें और लोग अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाये बिना और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से इसे बाहर खदेड़ने के लिए एकजुट हुए बिना नहीं रह सकते। भारतीय

जनता की ओर से हम वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर अमेरिकी आक्रमण की कड़ी भर्त्सना करते हैं और वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा इस संदर्भ में उठाये गये न्यायोचित कदम का समर्थन करते हैं।

अमेरिका की कल्पित कहानी

अमेरिकी आक्रमणकारियों ने आहत मासूमियत का नाटक करते हुए यह सफाई दी कि जब प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाज टोंकिन की खाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में गश्त लगा रहे थे, तब उत्तरी वियतनाम की गश्ती नौकाओं ने उन पर हमला किया; उसके जवाब में राष्ट्रपति जॉन्सन द्वारा अमेरिका के जंगी जहाजों को "जिन ताकतों ने उन पर आक्रमण किया, उन पर हमला करने और उन्हें नष्ट कर देने" के आदेश दिये गये और अमेरिकी सातवें बेड़े के जेट लड़ाकू विमानों ने वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों पर गोलीबारी और बमबारी की।

यह कल्पित कहानी कहां तक सच है? जिस किसी भी व्यक्ति के सिर में थोड़ा-सा भी दिमाग है, उसके लिए इस मनगढ़ंत कहानी को हजम कर पाना कठिन है। क्योंकि एक बच्चा भी समझता है कि चंद छोटी गश्ती नौकाओं के सहारे अमेरिकी सातवें बेड़े, जो शायद दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी बेड़ा है, को तबाह करने का प्रयास करना हद दर्जे का पागलपन और बेवकूफी होगी। क्या वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के जिन शासकों ने साम्राज्यवादियों के बहुत संगीन उकसावे पर भी अनुत्तेजित रहते हुए निर्णय लेने की अपनी परिपक्व क्षमता, राजनैतिक सूझबूझ और क्रांतिकारी यथार्थवादिता को दुनिया के सामने स्थापित किया है, वे इतना भी नहीं समझते जितना कि एक बच्चा भी समझता है। तो फिर क्यों वे चंद छोटी-छोटी गश्ती नौकाओं से अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने के दुस्साहस के काम में लिप्त होंगे? उत्तरी वियतनामी गश्ती नौकाओं द्वारा टोंकिन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की कहानी, जैसा कि पेंटागन ने रची है, पूरी तरह से अविश्वसनीय और बेसिर-पैर की कहानी है।

दुनिया के लोगों ने भी अमेरिका की इस कहानी की गणना एक अतिरंजित कहानी के रूप में की है। कम्बोडिया के राज्याध्यक्ष राजकुमार सिंहानुक ने अमेरिकी कहानी को सफेद झूठ कहकर अस्वीकार कर दिया है। पश्चिमी प्रेस, जिसमें अमेरिकी प्रेस शामिल है, उसके एक बड़े हिस्से

ने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 92 वर्षीय ब्रितानी दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल की प्रतिक्रिया भी वियतनामी प्रश्न पर अमेरिकी स्टैंड के बारे में आम लोगों की भावनाओं की ही सूचक है। लॉर्ड रसेल कोई साम्यवाद के समर्थक नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं को साम्यवादी विचारों और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का कट्टर दुश्मन समझते हैं। उन्होंने अपनी शक्तिशाली लेखनी का इस्तेमाल जीवनभर, जितनी भी भीषणता से और जैसे भी बन पड़ा, साम्यवाद के खिलाफ ही किया है। साम्यवाद-विरोधी ऐसी हस्ती भी वियतनाम पर अमेरिका की आक्रमणकारी नीति की भर्त्सना किये बगैर न रह सकी। द *टाइम्स* में छपे एक पत्र में उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे में गैर-साम्यवादी लोगों की ही संख्या ज्यादा है तथा उसका तटस्थ बने रहने का कार्यक्रम है। केवल वियतनाम में ही अमेरिका ने विदेशी सैन्य वाहिनियां तैनात कर रखी हैं; वही जेनेवा समझौते द्वारा मान्य चुनावों को कराने से मुकर रहा है; चारों ओर मार कर सकने वाली मशीनगनों से लैस तथा कुत्तों द्वारा गश्त किये जाने वाले और कंटीले तारों की बाड़ वाले कैम्पों में करीब अस्सी लाख लोगों को कैद कर रखा है; 1962 में ही गांवों पर 50,000 से अधिक हवाई हमले किये; उस देश को रासायनिक अस्त्रों और नापाम बमों से नष्ट किया; 1,60,000 लोगों को मार डाला; 7,00,000 को अपंग बना दिया और 3,50,000 लोगों को जेलों में ठूंस दिया है। दक्षिणी वियतनाम की सरकार और फौज अमेरिकी कठपुतलियां हैं, जिन पर 15,00,000 डॉलर प्रतिदिन खर्च किये जाते हैं। जब अमेरिका लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ चलाया जा रहा अपना अत्यंत बेरहम युद्ध समाप्त करेगा और 10 वर्ष पूर्व मानी गयी तटस्थता स्वीकार कर लेगा, तभी युद्ध समाप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वियतनाम को मिटा देने वाले नृशंसतापूर्ण अमेरिकी युद्ध के लिए अमेरिका को हमलावर करार देकर उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।'' पिछले अगस्त माह में उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी आक्रमण उसके दक्षिणी वियतनाम को तबाह कर देने वाले बेरहम युद्ध की ही निरंतरता है।

कोई भी व्यक्ति, जिसने अपनी बुद्धि और जमीर का डॉलर-देवता के हाथ सौदा नहीं कर डाला है, रसेल के इस विचार से सहमत होगा। लेकिन भारतीय प्रेस के एक हिस्से और जे.बी. कृपलानी व उनके हमसफरों की नुमाइंदगी में सोशल डेमोक्रेटों के एक तबके ने अमेरिकी व्याख्या को ध्रुव सत्य मान लिया है। अमेरिकी युद्ध सरदारों के सुर में सुर मिलाकर वे भी

''अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने'' और ''विश्व के इस क्षेत्र में साम्यवाद के बढ़ते कदमों को रोकने के उपाय के तौर पर अमेरिकी नेतृत्व के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया में 'बफर' राष्ट्र बनाने'' की तथाकथित जरूरत के लिए गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं। यह दक्षिण एशियाई देशों के लोगों की पूर्ण राष्ट्रीय आजादी के आंदोलनों को कुचलने तथा वहां अपने नव-औपनिवेशिक शोषण को जारी रखने के लिए अमेरिकी प्रभुत्व कायम करने के अमेरिकी साम्राज्यवादियों के प्रयासों का खुला समर्थन है। यह मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रेटों की खास चारित्रिक विशेषता है। इस मसले पर भारत सरकार का भी स्टैंड कम अमेरिका-परस्त नहीं है। अमेरिकी आर्थिक एवं सैन्य 'सहायताओं' पर सतत निर्भरता भारत को एशिया के साम्राज्यवाद-विरोधी खेमे से दूर धकेलती जा रही है तथा अमेरिका और उसकी एशियाई कठपुतली सरकारों के और भी करीब खींचती जा रही है। न बर्मा, न इंडोनेशिया, न ही कंबोडिया आज भारत के अच्छे दोस्त हैं, जबकि वे कभी भारत के घनिष्ठ मित्र होते थे और जो अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्राज्यवाद-विरोधी भूमिका निभा रहे हैं। मलेशिया के टुंकू अब्दूल रहमान, जो साम्राज्यवाद के पिठ्ठू हैं, ही केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारत के एकमात्र मित्र हैं। इस बढ़ते जा रहे अमेरिका-परस्त रवैये का नतीजा यह हुआ है कि भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्राज्यवादी ताकतों के अतिक्रमणात्मक हमले की कार्रवाइयों और षड्यंत्रों की शब्दों तक में भर्त्सना करनी छोड़ दी है और इस मामले में विशेषकर उत्तरी वियतनाम द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों पर पहले हमला करने की अमेरिका की मनगढ़ंत कहानी को सच मानकर खुद को अमेरिका की लाइन में खड़ा कर लिया है। निस्संदेह, यह देश के करोड़ों मेहनतकशों की साम्राज्यवाद-विरोधी आकांक्षा के साथ खुला विश्वासघात है।

टोंकिन की खाड़ी में उत्तरी वियतनाम द्वारा अमेरिका के युद्ध पोतों पर हमले की अमेरिकी दलील सफेद झूठ का पुलिंदा तो है ही, साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशिया में जो कुछ कर रहा है और विशेषत: इस मामले में जो कुछ किया है, उसके लिए कोई उचित कारण नहीं है। यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि अमेरिकी युद्धपोत वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की समुद्री सीमा के बाहर थे, तो हजारों मील दूर टोंकिन की खाड़ी में क्यों आ धमके थे और वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के तटों की क्यों गश्त लगा रहे थे? टोंकिन की खाड़ी

वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य और चीनी जन गणराज्य-दोनों देशों को काफी गहराई तक काटते हुए उनके तटों से सटी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपने युद्धपोतों को खाड़ी में भेजने का क्या कारण था? अगर किसी ताकतवर देश, जैसे कि सोवियत संघ, की नौसैनिक और वायु सैनिक टुकड़ियां मेक्सिको की खाड़ी में आ धमकतीं और अमेरिकी तटों की गश्त लगातीं तो अमेरिका कैसा महसूस करता और कैसे प्रतिक्रिया करता? क्या अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली उकसावे और शत्रुता की कार्रवाई नहीं समझता? तब अमेरिकी युद्धपोतों के टोंकिन की खाड़ी में आ धमकने पर जिस प्रकार उत्तरी वियतनाम और चीन ने प्रतिक्रिया की है, क्या वह गलत है? यकीनन, अमेरिकी युद्धपोतों के टोंकिन की खाड़ी में अकारण आ धमकने और वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य तथा चीनी जन गणराज्य के तटों पर उनके द्वारा गश्त लगाने को इन देशों के प्रति अमेरिका द्वारा खुल्लमखुल्ला की गयी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं समझा जा सकता, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसलिए वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के खिलाफ खुद अमेरिका ही उकसावे और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने का दोषी है, न कि वियतनाम।

विभिन्न देशों के शांति-पसंद लोगों को गुमराह करने के प्रयासों में अमेरिकी साम्राज्यवादी जोर-शोर से शांति में अपनी आस्था जता रहे हैं। किंतु क्या तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं? क्या कभी वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य या चीन या किसी अन्य समाजवादी राष्ट्र ने अपनी नौसेना या वायुसेना को अमेरिकी तटों पर हमला करने की धमकी दी है या अमेरिकी वायुसीमा का उल्लंघन किया है या अमेरिकी इलाकों पर गोलियां और बम बरसाये हैं? कोई भी समाजवादी देश ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। इसके विपरीत अमेरिका ही इन सब अपराधों का दोषी है। उसके युद्धपोत उत्तरी वियतनाम की समुद्री सीमा में घुसे, उसके लड़ाकू विमानों ने चीन, उत्तरी वियतनाम और सोवियत संघ समेत अन्य समाजवादी राष्ट्रों की वायुसीमाओं का उल्लंघन किया और वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के इलाकों पर गोले दागे और बम बरसाये; उसके युद्धपोत न केवल उत्तरी वियतनाम और चीन, बल्कि एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्रों के भी तटों की गश्त लगाते हैं; उसने उत्तरी वियतनाम की दो गश्ती नौकाओं को डुबोया है; उसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में दुस्साहसिक फौजी कार्रवाइयां,

तख्तापलट और साम्राज्यवादी षड्यंत्र रचने के साधनों के तौर पर सीटो, (SEATO), सेन्टो (CENTO), नाटो (NATO) इत्यादी आक्रामक, सामरिक ब्लॉक गठित किये हैं; उसने समाजवादी खेमे की घेराबंदी करने वाले अनगिनत फौजी अड्डे बनाये हैं ताकि हमला करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सके; वह क्यूबा को उसके स्वतंत्र होने के समय से ही धमकाता आ रहा है, अब वह उत्तरी वियतनाम पर जोरदार हमला करके उसे डरा रहा है; इत्यादि, इत्यादि। क्या ये सब शांति-नीति के संकेत हैं या ये खतरनाक हथकंडे अपनाने की चाल, शीतयुद्ध, छेड़खानी, फौजी दुस्साहस और आक्रमण की नीति के? उसने बिना किसी छेड़खानी के ही वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर हमला किया, अपनी पूर्व नियोजित योजना को पूरा किया, उस देश के तटीय इलाकों में तबाही मचायी और ये सब करके वह अपनी आहत मासूमियत के हावभाव लेकर और वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के खिलाफ अपने युद्धपोतों पर हमला करने के एक झूठे आरोप के साथ फरियादी बनकर यूएनओ के पास जाना चाहता था और चला भी गया।

आदि से अंत तक अमेरिका के क्रियाकलाप बताते हैं कि यह सब पूर्व-नियोजित था। कलकत्ता का अमेरिका-परस्त दैनिक अखबार *अमृत बाजार पत्रिका*, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मुखपत्र द *गार्जियन* को उद्धृत करके लिखता है: ''उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हवाई हमले और दक्षिण एशिया में सैन्य शक्ति की जो यह बहुत बड़ी हलचल हो रही है, यह सब बहुत सुनियोजित थी और केवल उचित अवसर की तलाश थी।'' अमेरिका का उत्तरी वियतनाम पर पिछले अगस्त में किया गया हमला बहुत पहले से सुनियोजित था, यह तथ्य अमेरिका की इस झूठी दलील की पोल खोल देता है कि उत्तरी वियतनाम पर उसका यह हमला अमेरिकी युद्धपोतों पर टोंकिन की खाड़ी में किये गये हमले की जवाबी कार्रवाई थी।

अमेरिका का मकसद

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक समाजवादी राष्ट्र वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर हमला करके अमेरिका ने एक जोखिम उठाया है। जोखिम यह था कि समाजवादी खेमा एक समाजवादी देश पर खामखाह जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किये गये अमेरिकी हमले का कारगर ढंग से प्रतिरोध करने के लिए ठोस सैन्य कदम उठा सकता था,

जिससे अमेरिकी साम्राज्यवादियों का खेल ही बिगड़ जाता और अमेरिका पर शिंकजा कस जाता। लेकिन सोवियत संघ के संभावित कदम के बारे में अमेरिका को यह अंदाजा था कि सोवियत संघ या यूं कहें कि समाजवादी खेमा वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर अमेरिकी हमले के बदले में कारगर तौर पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आयेगा, यह अंदाजा मुख्यत: क्यूबाई संकट के समय सोवियत संघ द्वारा लिये गये स्टैंड के हाल के तर्जुबे पर आधारित था। इसके बाद के तथ्यों ने साबित कर दिया कि संभावित सोवियत रवैये पर अमेरिका का अंदाजा सही था। अगर सीपीएसयू नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका की न्युक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसता तो यह अंदाजा गलत साबित हो जाता। अमेरिका ने निस्संदेह एक समाजवादी राष्ट्र पर हमला करके बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया था। किंतु सवाल यह है कि: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा जोखिम मोल क्यों लिया? दूसरे शब्दों में, इस हमले के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका का मकसद क्या था?

हम सब जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोल्डवाटर ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जॉन्सन को दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेषकर वियतनाम में ढुलमुल नीति अपनाने का दोषी ठहराया है, जिसकी वजह से गोल्डवाटर और उनके समर्थकों के मतानुसार अमेरिका और उसके सहयोगियों को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की ताकतों के हाथों एक के बाद दूसरी सैनिक पराजय का सामना करना पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप लाओस और वियतनाम में पूर्ण राष्ट्रीय आजादी, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय पुनर्मिलन, जैसा भी मामला हो, के लिए संघर्षरत साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतें और भी मजबूत होती जा रही हैं, जिससे अमेरिकी इजारेदारों और दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसकी सहयोगी प्रतिक्रियावादी ताकतों का मनोबल गिरा है, जो अमेरिका द्वारा प्रयोजित लाओस और वियतनाम में चल रहे सर्वनाश के युद्ध में अंतिम विजय की कोई आशा की किरण नहीं देख पा रहे हैं और जिससे अमेरिका को जन विद्रोह के खिलाफ अपने परम मसीहा के रूप में श्रद्धा से देखने वाली दुनिया की प्रतिक्रियावादी ताकतों के बीच अमेरिका की साख में कमी आती जा रही है। अमेरिका में ज्यादा जंगखोर हलके और सेना, जिनके प्रचारक गोल्टवाटर और उनके समर्थक बने फिर रहे हैं, जॉन्सन और उनके प्रशासन से दक्षिण-पूर्वी एशिया में, विशेषकर

वियतनाम और लाओस में कठोर नीति अपनाने की मांग कर रहे हैं। कठोर नीति से उनका आशय है दक्षिणी वियतनाम तक सीमित अमेरिका के हस्तक्षेप और सैन्य गतिविधियों को उत्तरी वियतनाम तक बढ़ाना। आने वाले चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की विजय के लिए, जॉन्सन को अमेरिकी मतदाताओं को दिखाना होगा कि दक्षिण-पूर्व एशिया, खास तौर से वियतनाम पर नीति चाहे जो कुछ भी हो, पर नर्म और ढुलमुल नहीं है। यदि अमेरिका के मतदाताओं में पर्याप्त राजनैतिक चेतना होती, तो उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया होता कि जॉन्सन प्रशासन के पास अमेरिकी इजारेदारों के साम्राज्यवादी स्वार्थों को स्थायी रूप देने के लिए ''दरिया में गनबोट उतारने यानी युद्ध की धमकी देने की कूटनीति'' और विदेशी भूमि पर आक्रमण करने ''की पुरानी साम्राज्यवादी चाल से अलग कोई दूसरी नीति नहीं है।'' लेकिन जैसाकि सभी पूंजीवादी देशों में होता है, उसी तरह अमेरिकी मतदाता भी चूंकि राजनैतिक रूप से सचेत नहीं हैं, इसलिए उनका देश एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी देशों में जिस नव-औपनिवेशिक व आक्रामक नीति का अनुसरण करता है, उससे वे अनभिज्ञ हैं और इसलिए अमेरिका में बारी-बारी शासन करने वाले इजारेदार गुट, जिनमें से एक की नुमाइंदगी जॉन्सन की डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे की गोल्डवाटर की रिपब्लिकन पार्टी करती है, आम अमेरिकी मतदाताओं को तथाकथित ''स्वतंत्र दुनिया'' की रक्षा के बहाने गुमराह करने, युद्धोन्माद भड़काने और प्रतिक्रांति को निर्यात करने, छेड़खानी करने, खतरनाक हथकंडे अपनाने की चालबाजी करने, युद्ध व पहले आक्रमण करने की नीति को जारी रखने को आसान पाते हैं। इसलिए, आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के स्वार्थ से दक्षिण-पूर्वी एशिया में सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका के वर्तमान शासकों ने नीतिविरुद्ध होने पर भी सुविधाजनक समझा। जॉन्सन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी चूंकि सरकार में हैं, इसलिए वे युद्ध को उत्तरी वियतनाम तक जितना भी फैलाना चाहें, इस दुस्साहसपूर्ण कार्य के संभावित गंभीर परिणामों की अवहेलना करना या इनको नजरअंदाज करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। अमेरिका के वर्तमान शासक जानते हैं कि वियतनाम में अमेरिका को अभी तक दक्षिणी वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सैन्य शक्ति का ही सामना करना पड़ रहा है और नतीजा यह हो रहा है कि इस सैन्य शक्ति ने, जो सैन्य उपकरणों से बहुत ही कम लैस है, अमेरिका और उसकी कठपुतली दक्षिणी वियतनामी सरकार की संयुक्त

सैन्य शक्ति के छक्के छुड़ा दिये हैं और दक्षिणी वियतनाम के तीन-चौथाई इलाके को मुक्त करा लिया है। ऐसे हालात में यदि अमेरिकी साम्राज्यवादी इस युद्ध को विस्तारित कर उत्तरी वियतनाम तक ले जाते हैं तो वे जानते हैं कि उन्हें न केवल उत्तरी वियतनाम, बल्कि चीन की भी अतिरिक्त सैन्य शक्ति का मुकाबला करना पड़ेगा, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि उत्तरी वियतनाम के साथ कोई भी युद्ध चीन के खिलाफ समझा जायेगा, या यूं कहें समाजवादी खेमे के खिलाफ समझा जायेगा; क्योंकि समाजवादी देश, उनके बीच चाहे जो भी वैचारिक मतभेद हों और कितने ही तनावपूर्ण संबंध क्यों न हों, वे अमेरिका द्वारा एक अन्य समाजवादी देश, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य, पर किये गये सर्वग्रासी हमले का संयुक्त रूप से विरोध किये बिना नहीं रह सकते। जॉन्सन और उनके मंत्री ऐसे युद्ध और उसके नतीजे को जानते हैं। कोरिया में क्या हुआ था, यह अभी तक उन्हें मालूम है। यदि केवल उत्तरी कोरिया की सेना और चीनी स्वयंसेवक (नियमित सेना नहीं) ही न केवल अमेरिकी, बल्कि दर्जनों अन्य साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों की सेनाओं को भी प्रशांत महासागर तक धकेल सकते हैं तो अमेरिका का समाजवादी खेमे में उत्तरी वियतनाम तक युद्ध फैलाने का सैन्य उलझाव विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की पूर्ण विजय एवं अन्य देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों और बड़े पूंजीवादी देशों के क्रांतिकारी संघर्षों में बड़ी प्रगति को सुनिश्चित करते हुए एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद की कब्र खोद देगा। अमेरिकी सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता का मिथक, जो सोवितय संघ के गलत स्टैंड की बदौलत केरेबियन संकट के बाद अमेरिका, राजनैतिक रूप से अचेत लोगों के बड़े हिस्से के बीच खड़ा करने में सक्षम हुआ है, वह पूरी तरह ध्वस्त हो जायेगा। साथ ही साथ यह अपने अस्तित्व के लिए जन अभ्युत्थान के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य शक्ति पर अंतिम गारंटी के रूप में भरोसा करने वाली विश्व की प्रतिक्रियावादी ताकतों के उस हौसले को भी पस्त कर देगा, जो कोरियाई युद्ध में अमेरिकी सेना की हुई पराजयों के समय नीचे गिर गया था, किंतु सोवियत संघ के गलत स्टैंड की वजह से अमेरिका की केरेबियन संकट में हुई विजय के बाद फिर काफी ऊपर उठ गया है। इसलिए अमेरिका के वर्तमान शासक उत्तरी वियतनाम तक युद्ध का विस्तार करके अपने दुस्साहसपूर्ण कारनामों के जरिये एशियाई सरजमीन पर अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगायेंगे। लेकिन गोल्डवाटर और उनके हिमायतियों

को करारी मात देने के लिए और आने वाले राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुछ तो करना ही था—यह जॉन्सन और शासन में विराजमान उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदरूनी समस्या थी।

और वह बाहरी समस्या क्या है जिसका जॉन्सन प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है? अमेरिका के मौजूदा शासकों को दक्षिण-पूर्वी एशिया की, विशेषकर वियतनाम और लाओस की प्रतिक्रियावादी अमेरिका-परस्त ताकतों के, जो कि राष्ट्रवाद-विरोधी ताकतों के रूप में वहां के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के विरुद्ध अमेरिका से गठजोड़ कर रही हैं, तेजी से गिरते मनोबल को ऊंचा उठाये रखना और बनाये रखना बहुत कठिन लग रहा है। अमेरिकी इजारेदारों, विशेषकर कुछ मौत के अमेरिकी सौदागरों के स्वार्थों की रक्षा के लिए हौसले में आयी यह गिरावट रोकनी पड़ेगी और अमेरिका-परस्त इन राष्ट्रवाद-विरोधी ताकतों में नयी जान फूंकनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा किये बिना विध्वंसकारी युद्ध, जो अमेरिका अपनी प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ लाओस और दक्षिणी वियतनाम में चला रहा है, को आगे जारी नहीं रखा जा सकता। और अगर इन देशों में गृहयुद्ध चालू नहीं रखे जा सके, अगर ये पूर्ण आजादी और राष्ट्रीय पुनर्मिलन या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए लड़ने वाली ताकतों के हक में बंद हो गये, तो अमेरिका को दक्षिण-पूर्वी एशिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिकी उपस्थिति और प्रभाव की सुरक्षा के लिए, दुनिया के इस भाग में जो पहले आक्रमण करने के युद्ध वह चला रहा है, उनको उसे धधकाये रखना होगा; ताकि दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका के नव-औपनिवेशिक हितों की लंबे अर्से तक पूर्ति होती रहे, इसके लिए दो युद्धरत सेनापतियों, जो गुलाम दक्षिणी वियतनाम और लाओस के कुछ हिस्से पर शासन कर रहे हैं, के बीच एकता करवाना, अमेरिका-परस्त राष्ट्रवाद-विरोधी ताकतों को पुनर्जीवित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली ताकतों के हाथों अमेरिकी सेना की पराजय के बाद हौसले को गिरने से रोकना और उनके हौसलों को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन अमेरिकी शासकों के लिए समस्या यह है कि यह किया कैसे जाये!

इसके अलावा, अगर अमेरिका युद्ध का विस्तार करके उत्तरी वियतनाम तक ले जाये, तो यह स्वाभाविक है कि सोवियत संघ की प्रतिक्रिया को पहले ही जान लेना चाहिए। अमेरिका द्वारा वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य

पर हमले की अवस्था में क्या सोवियत संघ महज हमले की भर्त्सना करने के लिए यूएनओ के मंच का इस्तेमाल करेगा या समुचित सैन्य कार्रवाई करके समाजवादी देश पर हमले का सकारात्मक रूप से प्रतिकार करेगा? अमेरिकी शासकों के लिए इस प्रश्न का उत्तर जानना अपनी भावी कार्य-प्रक्रिया को तय करने के लिए परम आवश्यक है। वियतनाम में लेकिन इसे कैसे जाना जाये? जॉन्सन और उनके सैन्य सलाहकारों के सामने यही समस्या थी।

जॉन्सन ने टोंकिन की खाड़ी में जो किया, उसका उद्देश्य अपने प्रशासन की इन्हीं समस्याओं का समाधान करना था। चूंकि अमेरिका के वर्तमान शासक ऊपर चर्चित कारणों की वजह से चीन अथवा सोवियत संघ अथवा समाजवादी खेमे से दक्षिण-पूर्वी एशिया में पूर्ण युद्ध में संलिप्त हो जाने का जोखिम मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके पास उत्तरी वियतनाम पर एक बहुत ही अल्कालिक आक्रमण के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन व वियतनाम की तुलना में अमेरिका की नौसेना और वायुसेना की जो श्रेष्ठता है, उसका इस्तेमाल करना ही एकमात्र विकल्प था। क्योंकि थल सेना की मदद से ऐसा करने से अमेरिका के लिए चीन के साथ थल-युद्ध में फंस जाने की नौबत आ सकती थी, जिससे वह हर हालत में बचना ही चाहेगा। इसलिए वह रणभूमि से पीछे हटने और फौजों को वापस बुलाने का रास्ता सदा खुला रखते हुए थल सेना से नहीं, बल्कि नौसेना और वायु सेना की मदद से हमला करना चाहता था ताकि चीन और समाजवादी खेमे के साथ सर्वात्मक संघर्ष में संलिप्त हो जाने से बचने के उद्देश्य से जब भी जरूरत पड़े, वह पीछे हट सके और अस्थायी सैन्य सफलता का अमेरिकी सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता के रूप में दुनिया के सामने दिखावा कर सके। अगर दक्षिण-पूर्वी एशिया में सोवियत संघ भी युद्ध में कूद पड़ा होता और अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का अपने बिरादराना समाजवादी देश उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले के खिलाफ उसकी रक्षा के लिए इस्तेमाल किया होता, तो असल में अमेरिकी नौसेना व वायुसेना की तथाकथित श्रेष्ठता ठहर नहीं सकती थी। लेकिन क्यूबाई संकट के अपने अनुभव पर अमेरिका के शासकों ने भरोसा करके अनुमान लगा लिया कि उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका के ऐसे हमले का सोवियत संघ सैनिक तौर पर प्रतिरोध नहीं करेगा। यह अनुमान सही साबित हुआ और सभ्यता के नियम-कायदों तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय कानून-कायदों और रीति-नीतियों को अनदेखा कर वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर

हमला करके अमेरिका ने जो करने की मन में ठान रखी थी, वह कर बैठा। इस तरह यह उद्देश्यपूर्ण सोचा-समझा जोखिम उठाकर गोल्डवाटर व उनके सहयोगियों का मुंह बंद करने में जॉन्सन सफल रहे हैं और अमेरिका के मतदाताओं को दिखा सके हैं कि वह रिपब्लिकन पार्टी की तुलना में उत्तरी वियतनाम या किसी भी समाजवादी देश पर सख्ती बरतने के मामले में कोई कम कठोर और कम सख्त नहीं है। अस्थायी सैन्य सफलता से भी जॉन्सन लाभ उठाने में कामयाब रहे हैं और अदंडित रहकर बेधड़क किसी भी समाजवादी देश को तबाह करने के लिए इस सफलता को अमेरिका की शक्ति और शौर्य के सबूत के रूप में प्रचारित करने और राजनैतिक रूप से अचेत लोगों के बीच यह भ्रम और अधिक पैदा करने में सफल रहे हैं कि अमेरिका अपनी मनमर्जी से जो कोई भी सैन्य कार्रवाई करे सोवियत संघ समेत किसी भी समाजवादी देश में उसका विरोध करने की ताकत और हिम्मत नहीं है और इस तरह वे इन देशों में युद्ध को जारी रखना, जो अब व्यर्थ समझ रहे थे उन अमेरिकी इजारेदारों और दक्षिणी वियतनाम व लाओस में प्रतिक्रियावादी ताकतों के एक हिस्से के गिरते मनोबल को ऊंचा उठाने, उन्हें और भी कृत संकल्पित होकर युद्ध चलाते जाने और दुनिया भर की प्रतिक्रियावादी ताकतों को शांति, लोकतंत्र और समाजवाद के खिलाफ अपना जेहाद चलाते जाने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल रहे हैं। अमेरिका की मौजूदा सैन्यीकृत अर्थव्यवस्था को अपने अति-उत्पादन के संकट को पार करने के अस्थायी जरिये के तौर पर उसके द्वारा जमा किये गये हथियारों और साजो-सामानों के जखीरे की खपत और उनकी पुनः आपूर्ति करने की जरूरत है। इसलिए ये मौत के अमेरिकी सौदागर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध के माहौल की तीव्रता बढ़ाने में जहां भी और जब भी संभव हो, स्थानीय सीमित युद्ध छेड़ने में अत्यंत दिलचस्पी रखते हैं। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले ने भी मौत के कुछ अमेरिकी सौदागरों के इस स्वार्थ की ही पूर्ति की है। हमारे उपरोक्त विश्लेषण की रोशनी में जांचे, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका के हमले का मकसद चीन या सोवियत संघ से समग्र युद्ध करना नहीं था, समाजवादी खेमे के साथ विश्वयुद्ध तो कतई नहीं। यह कुछेक खास सीमित सामरिक-राजनैतिक ध्येयों को प्राप्त करने के मकसद से उत्तरी वियतनाम पर बगैर उसकी ओर से कोई छेड़खानी किये ही अकारण हमले के रूप में सैन्य कार्रवाई करने के क्षेत्र में अमेरिका की कूटनीति के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं था।

सोवियत संघ की भूमिका

आइए, अब देखें कि ख्रुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने कैसा व्यवहार किया और जांचे कि उन्होंने सही कार्रवाई की या नहीं। सोवियत संघ ने वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर अमेरिकी हमले के खिलाफ औपचारिक विरोध प्रदर्शन के सिवा और इस मामले को यूएनओ में उठाने के सिवा व्यवहारतः कुछ नहीं किया। यहां तक कि यूएनओ में भी अपना प्रस्ताव अत्यंत बेमन से पेश किया था। ब्रितानी पूंजी और हमारे देश में भारतीय इजारेदारों के एक हिस्से के प्रवक्ता द *स्टेट्समैन* ने सोवियत संघ की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए लिखाः ''इस कार्रवाई के पीछे यह धारणा थी कि सोवियत संघ कोई प्रत्युत्तर नहीं देगा। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में बेमन से की गयी सोवियत दौड़धूप अमेरिकी अपेक्षाओं के ऐन अनुरूप थी।'' जॉन्सन को उम्मीद थी कि सोवियत संघ विरोध तो करेगा, मगर कारगर ढंग से जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा वह कुछ सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने का विशिष्ट ''ख्रुश्चेव सहायता कार्यक्रम'' लेकर आयेगा। सोवियत के व्यवहार से अमेरिका की इस उम्मीद की पुष्टि हुई है। यही वजह है कि राष्ट्रपति जॉन्सन और आमतौर पर साम्राज्यवाद-पूंजीवाद की प्रहरी पश्चिमी प्रेस ने सोवियत संघ द्वारा ''इसकी अपेक्षित यथार्थवादी नीति'' अपनाने के लिए इसकी तारीफ की है।

यह कैसे हुआ कि सोवियत संघ ने ठीक वैसा ही आचरण-व्यवहार किया, जैसा कि अमेरिका के साम्राज्यवादी उससे उम्मीद कर रहे थे? हमें लगता है कि सोवियत संघ की इस ढुलमुल नीति के लिए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएसयू) की संशोधनवादी लाइन पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता था? अधिकांशतः ताप-नाभिकीय युद्ध के भय की वजह से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उनके गलत नजरिये के सिवा और क्या बात थी, जिसने ख्रुश्चेव पंथी नेतृत्व को जवाबी कार्रवाई जैसे उपाय अपनाने से रोक दिया? वर्ना कुछ ही अंतर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र (आईसीबीएम) इस काम को करने के लिए काफी होते, जिनमें तमाम साम्राज्यवादी ताकतों के मुकाबले सोवियत संघ 'श्रेष्ठता रखता है। उत्तरी वियतनाम पर हमले में रत अमेरिका के युद्धपोतों और विमानों को अंतर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों (आईसीबीएम) की मदद से नष्ट करने और अमेरिकी आक्रमण पर विराम लगा देने के बाद सोवियत संघ यूएनओ में जा सकता था और दुनिया के

तमाम लोगों को यह समझा सकता था कि चूंकि अमेरिका के साम्राज्यवादियों ने शांतिपूर्ण समाजवादी देश पर तमाम अन्तर्राष्ट्रीय कायदे-कानूनों का उल्लंघन कर हमला करने की जुर्रत की थी, इसलिए वह जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया गया था और साम्राज्यवादी अगर अपना हमला जारी नहीं रखते, तो जवाबी कार्रवाई को आगे जारी रखने का उसका भी कोई इरादा नहीं था। वह अमेरिकी आक्रमणकारियों को यह धमकी दे सकता था कि अगर उन्होंने उत्तरी वियतनाम पर नये सिरे से हमला किया, तो इसका समुचित सैन्य कार्रवाई से डटकर मुकाबला किया जायेगा और साथ ही साथ इससे साम्राज्यवादी जंगखोरों पर शांति थोप देन के लिए अमन-पसंद जनता की शक्ति में इजाफा होता। अगर सोवियत संघ ने यह सही कदम उठाया होता, तो इसका नतीजा क्या हुआ होता? सोवियत खेमे की तुलना में अमेरिकी सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता का जो भ्रम क्यूबाई संकट के समय से ताप-नाभिकीय युद्ध के डर से ब्लैकमेल होने के चलते सोवियत संघ के गलत स्टैंड की वजह से अमेरिका विश्व की प्रतिक्रियावादी ताकतों के बीच पैदा करने में सक्षम हो गया था, वह भ्रम टूट गया होता। फलस्वरूप विश्व की प्रतिक्रियावादी ताकतों के हौसले पस्त हो गये होते और क्यूबाई संकट के बाद से उनकी जो आक्रामकता बढ़ गयी थी, वह ठंडी पड़ गयी होती तथा अभी-अभी अमेरिकी की ओर झुकी हुई कुछ गुट निरपेक्ष एशियाई देशों की विदेश नीति पलट गयी होती। प्रतिक्रियावादी ताकतों के अलावा राजनैतिक रूप से अचेत लोग भी हैं, जो भले ही गलत हों पर ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि अमेरिका द्वारा विदेशी भूमि पर किसी हमले का सैन्य प्रतिरोध न करने की सोवियत संघ की इच्छा के पीछे शांति कायम करने की इच्छा न होकर उसकी सैन्य कमजोरी है। दूसरे शब्दों में, ये लोग सोवियत संघ की शांति नीति के ख्रुश्चेवी तरीके को ''अमेरिका की कठोर नीति और सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता के सामने पीठ दिखाना'' समझते हैं। अगर सोवियत संघ ने अमेरिकी हमले का मजबूत सैन्य कार्रवाई से कारगर रूप से प्रतिरोध किया होता, तो अनभिज्ञ लोगों के इस तबके को निस्संदेह यह विश्वास दिला दिया जाता कि सोवियत संघ की शांति कायम रखने की इच्छा उसकी कमजोरी के कारण नहीं थी और यह कि सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता के बावजूद सोवियत संघ सचमुच शांतिप्रिय देश है, क्योंकि वे खुद देख लेते कि अमेरिका को हराने की सैन्य क्षमता होने के बावजूद सोवियत संघ वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य पर

अन्यायपूर्ण अमेरिकी हमले का प्रतिरोध करने के लिए जितना सैनिक तौर पर जरूरी था, उससे आगे एक इंच भी नहीं बढ़ा। वह दुनिया को वस्तुगत रूप से साफ-साफ दिखा सकता था कि विभिन्न पार्टियों के बीच चाहे जितने भी मतभेद क्यों न हों और विभिन्न समाजवादी देशों के बीच चाहे जितने भी तनावपूर्ण संबंध क्यों न हों, पर साम्राज्यवादी ताकतों को इन मतभेदों से फायदा उठाने की बात तो दूर रही, अटकलें लगाने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा और यह कि समाजवादी देश पर हमले की तो बात ही क्या है, किसी भी विदेशी भूमि पर किसी भी साम्राज्यवादी हमले के विरुद्ध समाजवादी खेमा एक अखंड इकाई के रूप में एकजुट होकर संयुक्त रूप से काम करेगा। यह मिसाल अमेरिकी जंगखोरों को यह सबक सिखा देती कि अगर उन्होंने किसी भी समाजवादी देश को छुआ, तो उनके हाथ जल जायेंगे और उन पर अपनी औकात में रहने का असर डालती। सोवियत संघ का यह कदम और तो और दुनिया भर के औपनिवेशिक देशों और पराश्रित देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के पक्ष में अत्यधिक ताकत भर देता, खासकर वियतनाम और लाओस तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के लोगों को उनकी राष्ट्रीय जनवादी क्रांति को पूरा करने और साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में क्रांतिकारी संघर्षों को बढ़ावा देने में जबरदस्त मदद देता। तब विश्व शांति और कमजोर देशों की आजादी के सच्चे रक्षक तथा राष्ट्रीय आजादी के सच्चे रक्षक तथा राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ने वाले गुलाम और औपनिवेशिक देशों के लोगों के सक्रिय मददगार के रूप में सोवियत संघ का अभिनंदन किया गया होता। सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका के सैन्य हमले से खुले इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। वह केवल विरोध जताने यूएनओ में गया और वह भी अमेरिकी उम्मीदों के अनुरूप औपचारिक ढंग से।

हमें पता है कि सोवियत संघ का ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व हमारे उपरोक्त सुझावों के खिलाफ क्या दलील पेश करेगा। इस नेतृत्व ने पहले भी यह दलील पेश की थी और अब इस मामले में भी यही दलील पेश करेगा कि अगर सोवियत संघ ने जवाबी हमला किया होता, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ताप-नाभिकीय युद्ध छिड़ गया होता, इस खतरे से समाजवादी देश की तो बात दूर रही, कोई भी समझदार व्यक्ति आंख मूंदे नहीं रह सकता। चूंकि सोवियत संघ ताप-नाभिकीय युद्ध के खिलाफ है और वह कभी भी इसे पहले शुरू नहीं करेगा, कैसे शुरू कर सकता है जब

तक पहले अमेरिका शुरू न करे? क्या ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व को कभी यह बात सूझी है कि उनका यह स्टैंड कितना स्वविरोधी है? एक तरफ तो युद्ध और शांति के सवाल पर चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि आज की बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में साम्राज्यवादी अब युद्ध छेड़ने के काबिल नहीं हैं, दूसरी तरफ, क्यूबाई संकट या टोंकिन की घटना पर अपने गलत स्टैंड की सफाई में वे कहते हैं कि अगर सोवियत संघ ने अमेरिका के हमले का सैन्य प्रतिरोध किया होता, तो साम्राज्यवादियों ने ताप-नाभिकीय यद्ध छेड़ दिया होता।

फिर ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व का यह कहना क्या सही है कि अगर सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका के हमले के खिलाफ दृढ़ सैन्य उपाय बरते होते, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ताप-नाभिकीय युद्ध छिड़ जाता? हम ऐसी सोच-समझ को पूरी तरह गलत करार देते हैं। अमेरिका के मकसदों पर चर्चा करते समय हमने पहले ही बताया है कि उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमला समाजवादी खेमे के खिलाफ ताप-नाभिकीय युद्ध या विश्वयुद्ध छेड़ने की बात तो दूर रही, अमेरिका और सोवियत संघ या चीन के खिलाफ सैन्य शक्ति की समग्र जोर आजमाइश करने के उद्देश्य से भी नहीं किया गया था। यह सैन्य कार्रवाई के क्षेत्र में केवल कुछ खास सीमित सामाजिक-राजनैतिक उद्देश्यों पर लक्षित अमेरिकी कूटनीति का विस्तार मात्र था। इसलिए अगर अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की मदद से सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम पर हमला करने वाले अमेरिकी युद्ध पोतों और विमानों को नष्ट कर दिया होता और समाजवादी देश पर अमेरिका के हमले का कारगर प्रतिरोध किया होता, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोई लंबा और बड़े पैमाने का युद्ध भी शुरू नहीं हुआ होता, सोवियत नेतृत्व द्वारा अनुमानित ताप-नाभिकीय युद्ध की तो बात दूर रही। इसके अलावा, अमेरिका के छिपे मंसूबे को सोवियत संघ नाकाम कर सकता था और पराधीन व औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आजादी आंदोलनों और बड़े पूंजीवादी देशों में चल रहे क्रांतिकारी संघर्षों और शांति के पक्ष में स्थिति को पलट दे सकता था।

लेकिन अमेरिका के इस सीमित सैन्य दुस्साहस और अन्य स्थानीय व आंशिक युद्धों का सही-सही अध्ययन कर पाने में सोवियत नेताओं की विफलता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ताप-नाभिकीय युद्ध या फिर साम्राज्यवादी खेमे और समाजवादी खेमे के बीच विश्वयुद्ध छिड़ जाने

का खतरा उनके दिलो-दिमाग पर मंडराते रहने का कारण बन गयी। ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व की ओर से यह अवास्तविक और अतिरंजित भय की भावना उन्हें अमेरिका की ताप-नाभिकीय युद्ध या विश्वयुद्ध के खतरे की न्यूक्लीयर ब्लेकमेल की नीति का शिकार बना रही है और अमेरिकी साम्राज्यवादियों को अनावश्यक और एकतरफा रियायतें दिला रही है। यह एक वास्तविक सत्य है, जिसको कितनी भी क्रांतिकारी लफ्फाजी की जाये, वह झूठला नहीं सकती। हमने *सोशलिस्ट यूनिटी* के फरवरी, 1963 के अंक में एक लेख में व्याख्या की थी कि कैसे केरेबियन संकट पैदा करने के पीछे अमेरिका के मकसद का आकलन कर पाने में सोवियत नेता विफल रहे थे। वहां भी सोवियत नेताओं को विश्वयुद्ध की ओर ले जाने वाले ताप-नाभिकीय युद्ध का खतरा नजर आया था, जबकि ऐसा कोई खतरा नहीं था और उन्होंने अमेरिका को अनावश्यक और एकतरफा रियायतें दी थीं। तब से अमेरिका के शासक अच्छी तरह से समझ गये हैं कि सोवियत नेतृत्व का दिमाग कैसे काम करता है और उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि सोवियत संघ दृढ़ सैन्य कदम उठाकर सोवियत संघ के सिवा किसी भी देश पर किसी भी अमेरिकी हमले या आक्रमण का कारगर विरोध नहीं करने वाला है। इस जायजे ने अमेरिकी दखलअंदाजियों, हमलों या कब्जा करने के आक्रमणों का सोवियत संघ द्वारा सैन्य प्रतिरोध करने के मामले में नाभिकीय युद्ध कर देने की धमकी देने और सोवियत संघ की प्राय: आत्मसमर्पण के समान निष्क्रियता का फायदा उठाते हुए जहां पर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना सापेक्ष रूप से ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में हैं, वहां स्थानीय व आंशिक युद्धों के जरिये दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखअंदाजी, हमला या विदेशी भूमियों पर कब्जा जमाने के आक्रमण करने की अपनी नीति को जारी रखने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हौसले बढ़ा दिये। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमला अमेरिका के शासकों द्वारा सोवियत नेताओं के मन की कार्यप्रक्रिया को सही ढंग से पढ़ लेने का ही स्वाभाविक परिणाम है। सोवियत नेताओं को यह एहसास होना चाहिए कि अगर वे अमेरिका की नाभिकीय ब्लेकमेल की चालों को सही ढंग से नहीं समझ सके और विश्वयुद्ध के अपने अवास्तविक और अतिरंजित भय और ताप-नाभिकीय युद्ध-आतंक पर विजय नहीं पा सके, तो हो सकता है कि उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमला अखिरी न हो और अमेरिकी साम्राज्यवादी नाभिकीय युद्ध की धमकी देकर दूसरे देशों के

अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी करना जारी रखे और उन पर आक्रमण भी कर दे, जो औपनिवेशिक व अर्द्ध औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों और साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों मे चल रहे क्रांतिकारी संघर्षों के लिए नुकसानदेह होंगे। टोंकिन की खाड़ी में दो अनजान गश्ती नौकाओं पर हमला करके और उन्हें डुबो करके, जैसाकि पश्चिमी प्रेस ने बताया, अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा शुरू की गयी ये ताजा छेड़खानियां दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका द्वारा किये जाने वाले और भी दुस्साहसों की संभावना को इंगित करती हैं। तब क्या यह सही होगा कि उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका के हमले पर सोवियत स्टैंड को उनके ''शांति और समाजवाद की ताकतों द्वारा युद्ध के पैरोकारों पर शांति थोप देने'' के संघर्ष की मिसाल के रूप में संज्ञा दी जाये, जैसे कि दावे के साथ ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व ने दी है? नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। क्योंकि, शांति और समाजवाद की ताकतों द्वारा युद्ध के पैरोकारों पर शांति थोप देना साम्राज्यवादी ताकतों का दुस्साहसिक कार्यों में लिप्त होने और दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी करने से रोकते हुए शांति के लिए संघर्षों, गुलाम और औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आजादी आंदोलनों और पूंजीवादी देशों के मजदूरों व अन्य शोषित-पीड़ित लोगों की समाजवाद के लिए क्रांतिकारी लड़ाइयों को बल दिये बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्यूबाई संकट पर या उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले पर सोवियत स्टैंड इन अमेरिकी साम्राज्यवादियों की आक्रामकता में क्या थोड़ी-सी भी कमी ला पाया है? नहीं ला पाया है, बल्कि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगखोर हलकों को अपने दुस्साहसों में और भी बेपरवाह बना दिया है।

न्यूक्लीयर ब्लेकमेल की अमेरिकी चाल के अपने गलत अध्ययन-विश्लेषण के चलते सोवियत नेताओं के दिलो-दिमाग में साफ तौर पर पैदा हुए ताप-नाभिकीय युद्ध-आतंक की वजह से एक खास युद्ध छिड़ने व एक खास शांति के संरक्षण से संबंधित विशेष मामलों में एक के बाद दूसरी गलतियां करते जाने के अलावा सोवियत नेता अन्य समाजवादी देशों और सोवियत संघ के बीच द्वेषजनक अप्रिय विभेद पैदा करने के भी दोषी हैं। अगर अमेरिका ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया होता, तो सोवियत संघ क्या कार्रवाई करता? क्या वह सिर्फ यूएनओ में जाता और वहां अमेरिका के खिलाफ अपना एक औपचारिक विरोध ही दर्ज कराता तथा आक्रमणकारी के खिलाफ तमाम सैन्य कार्रवाइयों को ईमानदारी से

टाल जाता, जैसे कि उसने उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले के मामले में किया, या फिर वह पहले अमेरिका के विरुद्ध जवाबी सैन्य कार्रवाई करके आक्रमणकारी को हमला बंद करने के लिए मजबूर करता और फिर यूएनओ में गया होता और अमेरिका की छेड़खानी, ब्रिंकमेनशिप यानी युद्ध धमकी, युद्ध और आक्रमण की नीति का भंडाफोड़ करता? हमें इसमें कोई शक नहीं है कि सोवियत संघ ने निश्चय ही यह रास्ता अपनाया होता, जैसे कि उसने कुछ साल पहले अपनाया था, जब अमेरिकी विमानों ने उसकी वायु सीमा का उल्लंघन किया था। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के अपने सीमाक्षेत्रों पर हमला, गोलीबारी और बमबारी कर दी होती, जैसे कि इसने एक अन्य समाजवादी देश वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के मामले में की थी, तो इस आशंका ने उसे अमेरिकी हमले और आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं रोका होता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई तो ताप-नाभिकीय युद्ध या विश्वयुद्ध की ओर भी ले जा सकती है, जो दलील अब सोवियत नेताओं द्वारा उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले पर अपने स्टैंड की सफाई देने के लिए दी जा रही है। फिर क्यों एक बेवजह हमले के विरुद्ध जवाबी सैन्य कार्रवाई करने के मामले में सोवियत संघ और वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच द्वेषजनक भेदभाव पैदा किया गया? क्या इसलिए कि वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य सोवियत संघ नहीं है, अतः उस पर अमेरिकी हमले से सोवियत संघ का कोई सरोकार नहीं है? या फिर क्या इसलिए कि वह एक छोटा देश है, अतः कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? या फिर क्या इस वजह से कि विभिन्न समाजवादी पार्टियों के बीच चल रहे मौजूदा वैचारिक संघर्ष में वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य ने आमतौर पर चीन के स्टैंड का समर्थन किया है, अतः अमेरिकी हमले का प्रतिरोध न करके उसे एक सबक सिखाया जाये? अगर सोवियत नेता पहले वाले दोनों सोच-विचारों से प्रेरित हुए होते, तो अपने इस व्यवहार से वे यह साबित कर देते कि सोवियत संघ की रक्षा उनकी नजर में किसी भी अन्य समाजवादी देश की तुलना में ऊंचा स्थान रखती है। यह एक गैर साम्यवादी दृष्टिकोण है। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना से ओत-प्रोत और उससे निर्देशित किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े या छोटे सभी समाजवादी देश बराबर होते हैं और वे सब उसी समाजवादी भाईचारे के परिवार के होते हैं। इसलिए किसी भी समाजवादी देश पर हमला उनके अपने देश पर

हमला समझा जाना चाहिए, जिसके लिए आक्रमणों का कारगर ढंग से प्रतिरोध करने और उनको विफल कर देने के लिए सभी समाजवादी देशों को सामूहिक कदम उठाने की जरूरत होती है। इस बात को न मानना जैसे कि सोवियत नेताओं ने अमेरिकी हमले का प्रतिरोध करने के मामले में दो समाजवादी देशों के बीच द्वेषजनक भेदभाव करके नहीं माना है, हो सकता है अनजाने में हो, पर प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद से ग्रस्त हो जाना है, जो कि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना के असंगत है। लेकिन अगर सोवियत नेता तीसरे सोच-विचार से प्रेरित हुए हैं, अर्थात अगर उन्होंने विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच चल रहे वैचारिक संघर्ष में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की सैद्धांतिक लाइन का वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थन न करने की वजह से इस साम्राज्यवादी हमले का विरोध न करके उत्तरी वियतनाम को सबक सिखाने की सोची है, तो फिर जितना कम कहा जाये उतना ही बेहतर है। क्योंकि उस मामले में तो सोवियत नेतृत्व सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और समाजवादी भाईचारे के साथ घोर विश्वासघात करने और समाजवाद व साम्यवाद के दुश्मन को ही शोभा देने वाली करतूत करने का दोषी है।

इसके अलावा, ख्रुश्चेवपंथी नेता लगातार यह कहते आये हैं कि सोवियत संघ के सिवा किसी भी समाजवादी देश को नाभिकीय हथियार विकसित करने और रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तमाम समाजवादी देशों को साम्राज्यवादी हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त नाभिकीय अस्त्र हैं और वह तमाम समाजवादी देशों की प्रतिष्ठा व सुरक्षा के लिए जमानतदार है। हालांकि हमें विश्वास है कि सोवियत संघ के पास समाजवादी देशों पर किसी भी संभावित साम्राज्यवादी हमले से उन्हें बचाने के लिए प्रर्याप्त संख्या में नाभिकीय अस्त्र हैं, फिर भी हम इस सोवियत स्टैंड को गलत मानते हैं कि कोई अन्य समाजवादी देश नाभिकीय हथियार विकसित न करे और न रखे। हमारा मत है कि जब तक साम्राज्यवादी देश नाभिकीय अस्त्र बनाते और जमा करते रहेंगे और जब तक नाभिकीय परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाता व सभी नाभिकीय हथियारों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक अन्य समाजवादी देशों को भी, खासकर जो इन्हें बनाने का खर्च वहन कर सकते हैं, उन्हें ये नाभिकीय हथियार विकसित करने और रखने चाहिएं। इसके अलावा, उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले के संबंध में सोवियत संघ के आचरण-व्यवहार के संदर्भ

में उसके द्वारा दिये गये आश्वासन को जांचें-परखें तो उस आश्वासन की क्या कोई वास्तविक कीमत है? इसके अलावा, क्या किसी समाजवादी देश की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति केवल दिखावे या केवल उसकी अपनी ही रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाये या इसका कोई क्रांतिकारी महत्व भी है और इस विषय में कमजोर राष्ट्रों व अन्य समाजवादी देशों पर साम्राज्यवादियों द्वारा हमला कर दिये जाने की दशा में इसका कोई अन्तर्राष्ट्रीय फर्ज भी बनता है? यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी समाजवादी देश अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और वहां समाजवाद कायम करने के उद्देश्य से किसी भी पूंजीवादी देश पर पहले हमला करके उसे हराने के लिए कभी नहीं करता है। न ही कोई समाजवादी देश किसी अन्य देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए कभी खतरा पैदा करता है। क्रांति के निर्यात का विचार मार्क्सवादी-लेनिनवाद के विपरीतधर्मी है। परन्तु जब एक साम्राज्यवादी ताकत मिलिटरी के द्वारा हमला करे या किसी कमजोर देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता को फौजी दखलअंदाजी या हमले से खतरे में डाले या हथियारों के बल पर पराधीन और औपनिवेश देशों के लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को तबाह करने की कोशिश करे, तो क्या समाजवादी देश को अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल ऐसी साम्राज्यवादी साजिशों को नाकाम करने के लिए कारगर ढंग से नहीं करना चाहिए? आज की बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने समाजवादी खेमे को यह मौका दिया है और उस पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह साम्राज्यवादियों की ऐसी दुस्साहसिक कार्रवाइयों को विफल करे और उन पर शांति थोप दे। ऐसा नहीं करने का अर्थ होगा समाजवादी खेमे को जो ऐतिहासिक कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उसे पूरा करने से इनकार कर देना।

इसलिए जब अमेरिकी युद्धपोत और विमान एक समाजवादी देश पर हमला करने में व्यस्त थे, तो सोवियत संघ एक मूक दर्शक बना रहकर समाजवादी खेमे के नेता के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में बुरी तरह विफल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूएनओ में भी सोवियत संघ सही तरह से कार्रवाई करने में विफल रहा। यूएनओ में सोवियत संघ के प्रस्ताव रखने में बरती गयी बेदिली और बेपरवाही के अलावा, भी एक बात यह है कि उत्तरी वियतनाम के साथ अमेरिकी कठपुतली दक्षिणी वियतनाम को यूएनओ में बुलाने के अमेरिकी प्रस्ताव से सोवियत प्रतिनिधि कैसे सहमत हो गये थे?

अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला किया था—यह एक तथ्य था, हकीकत थी। हालांकि अमेरिकी ने आरोप लगाया है कि उत्तरी वियतनाम ने अमेरिकी युद्धपोतों पर पहले हमला किया था। लेकिन जो भी मामला रहा हो, अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के झगड़े में दक्षिणी वियतनाम कहां से आ गया? उत्तरी वियतनाम के खिलाफ झूठा और कुत्सित प्रचार करने के लिए दक्षिणी वियतनाम को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करके अमेरिका के इसे यूएनओ में बुलाने के प्रस्ताव के लिए सहमत होकर सोवियत संघ ने अमेरिका के इस खेल को क्यों चुपचाप स्वीकार कर लिया? केवल इतनी ही बात नहीं है। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हमले का कारगर विरोध करने के लिए सैन्य कार्रवाइयां करने और यूएनओ में सही पक्ष प्रस्तुत करने की बात तो दूर रही, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व ने किसी समाजवादी देश पर हुए अमेरिकी हमले का प्रतिवाद करने के लिए अपने खुद के देश में भी प्रदर्शन तक आयोजित नहीं किया, विरोध की आंधी की बात तो छोड़िए, जोकि उसे पूरी दुनिया में संगठित रूप से उठानी चाहिए थी। अमेरिकी साम्राज्यवादियों को अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बेनकाब करने, अलग-थलग करने और किनारे करने के लिए गंभीर प्रयास करने के बजाय ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व ने इसके उलट बड़े ही गैर-जिम्मेदाराना ढंग से दोनों पक्षों से अपील की है कि दोनों आपस में छेड़खानी न करें मानो अमेरिका नहीं, बल्कि कोई और इस छोड़खानी में लिप्त हो। क्या यह अपील, निहित अर्थ में आक्रमणकारी और पीड़ित को बराबर दर्जे पर नहीं रख देती? जबकि स्वीकृत सत्य यह है कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने बगैर उत्तरी वियतनाम द्वारा कोई छेड़खानी किये ही उस पर हमला कर दिया था, ख्रुश्चेवपंथी नेतृत्व के आलोचकों पर युद्ध भड़काने के आरोप मंढ़ने, कलंकित करने और इस प्रकार उन्हें विश्व साम्यवादी मंच से अलग-थलग करने के अलावा यह अपील किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? क्या हमलावर साम्राज्यवादी देश और हमले के शिकार हुए समाजवादी देश को इस तरह एक पलड़े में रख देना सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ विश्वासघात नहीं है? सोवियत नेताओं को इन सवालों का जवाब देकर सारे कम्युनिस्टों को संतुष्ट करना होगा।

सर्वप्रथम नवंबर, 1963 में
सोशलिस्ट यूनिटी में प्रकाशित।